Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES

(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22, अंक 2 रविवार फरीदाबाद, 16 - 30 नवम्बर, 2008 फोन : -2410196,9868858632 सहयोग राशि 1 रुपया

मैं टाइगर नहीं, गीदड़ हूं : डीजीपी

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 2 नवम्बर को हरियाणा के डीजीपी रंजीव दलाल ने ज़िले भर के इन्सपेक्टरों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों की एक बैठक में दारुण विलाप के दौरान कहा कि जब वे पंचकूला से चलते हैं तो विभागीय प्रथानुसार वायरलेस पर यह संदेश प्रसारित होता है कि टाइगर निकल लिया है। वास्तव में हरियाणा पुलिस के प्रमुख का कोड शब्द टाइगर है। उन्होंने स्वयं कहा कि वे काहे के टाइगर हैं ? वे कोई टाइगर-वाइगर नहीं, वे तो गीदड़ हैं। बेशक रंजीव दलाल ने यह बात अब स्वीकार की है, लेकिन उनको नज़दीक से जानने वाले तब से जानते हैं जब ये भिवानी में एसपी थे। उस वक्त इनके रीडर त्यागी द्वारा चलाई गोली से सूंडा नामक एक मामूली चोर मर गया था जिसके उपलक्ष्य में इन्हें बहादुरी का तग़मा मिला था। अम्बाला में बतौर डीआईजी तैनाती के दौरान टोची बदमाश जब इन्हें टेलीफ़ोन पर धमकी दिया करता था तो उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। कोठी को किले के रूप में परिवर्तित करा दिया गया था। इत्तफ़ाक से पंजाब पुलिस के हाथों मारे गये उस टोची की लाश को इन्होंने अपने पहुंचने तक उठाने नहीं दिया ताकि लाश को सार्वजनिक तौर पर ठोकरें मार कर अपनी भड़ास निकाल सकें।

2 नवम्बर की इस बैठक में इन्होंने अन्य बातों के अलावा कहा कि ये सारे इन्सपेक्टर जनता को लूटने-खाने के अलावा कोई काम नहीं करते। ये जो डीएसपी बैठे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट व निकम्मे हैं। ये लोग इन्सपेक्टरों को केवल परवाना-नोटिस लिख देते हैं जिसे अगले दिन इन्सपेक्टर आ कर इनके रीडरों से मिल कर ठीक ठाक करा लेते हैं। ये डीएसपी बजाये परवाने लिखने के क्यों नहीं खुद मौके पर जाते, क्यों नहीं खुद ज़िमनियां देते ? इसी संदर्भ में अपने एक एडीजीपी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब वह खुद थानों में जा-जा कर केस, फाइलें व ज़िमनियां देखता है तो ये डीएसपी और एसपी क्या करते हैं ?

> *जिस फ़ौज का जनरल ही गीदड़ हो जाये तो उस फ़ौज की क्या स्थिति होगी ? वे तो फिर खरगोश ही हो जायेंगे जो कुत्तों से भी छिपते फिरेंगे ? यह बात काफी हद तक सही है कि पुलिस महकमे में निकम्मे, नालायक, भ्रष्ट और लुटेरे भरे पड़े हैं, परन्तु इसका हल विलाप करने से तो नहीं निकलेगा।*

थाना सराय ख्वाजा के एक केस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की कार से एक शराबी को मामूली चोट के मामले को बजाये कानूनी तरीके से निपटाने के उसे सौदेबाजी के लिए कितने ही दिनों से लटकाये बैठे हैं। यह मामला डॉ. त्रेहन के एक जूनियर डॉक्टर से सम्बन्धित था। उस डॉक्टर ने बजाय पुलिस को रिश्वत देने के डॉक्टर त्रेहन को बता दिया जिन्होंने आगे तमाम उच्चाधिकारियों को सारा मामला बता दिया। हां, यदि यह मामला त्रेहन से सम्बन्धित न हो कर किसी जन साधारण का होता तो काहे को डीजीपी ने सुनना था और काहे को किसी उच्चाधिकारी ने इसमें दखलंदाजी करनी थी, स्थानीय पुलिस हमेशा की तरह वसूली करके मामले को निपटा देती। डीजीपी अथवा अन्य उच्चाधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता एक नहीं तो दो प्रतिशत लोग ही तो रखते हैं, शेष 98 प्रतिशत लोग तो बेचारे रिश्वत दे कर ही अपना काम निकालने को मजबूर हैं ही। बुरी तरह से झल्लाते हुए डीजीपी ने बताया कि उन्होंने दो हवलदारों का तबादला भोंडसी, आइआरबी का कर दिया तो उन्होंने 64 सूमो गाड़ियां पब्लिक की भर कर सीएम के दरवाजे पर लगा दी। उन्होंने यद्यपि यह नहीं बताया कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन समझा जा सकता है कि सीएम ने उनसे पूछा होगा कि इन हवलदारों का तबादला ऐसी जगह क्यों किया जहां ये जाना नहीं चाहते ? और यह भी संभव है कि सीएम के आदेश पर डीजीपी ने थूका हुआ चाट भी लिया हो।

उन्होंने यह भी रहस्योद्घाटन किया कि वे अपने गांव में नहीं घुस सकते। जब वे वहां जाते हैं तो लोग इनके कपड़े फाड़ते हैं। यद्यपि उन्होंने पूरी बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन समझा जा सकता है कि गांव वालों को इनसे जो आशायें थीं, वे जब

शेष पृष्ठ 2 पर

जजों के रिश्तेदारों द्वारा वकालत पर रोक ?

न्याय के व्यापार में जजों के रिश्तेदार काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। जिस वकील का बाप, चाचा, मामा, साला या बहनोई हाई कोर्ट का जज हो तो फिर उस हाई कोर्ट तथा उसके दायरे आने वाली मातहत जिला अदालतों में तो उसकी चांदी ही चांदी है। और अक्षय भान जैसा वकील जिसका बाप सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो फिर तो कहने ही क्या। मात्र 6-7 साल की वकालत और करोड़ों की इनकम टैक्स रिटर्न।

इस तरह का यह कोई इक्का-दुक्का उदाहरण नहीं है। लगभग प्रत्येक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जज का कोई न कोई निकट संबंधी न्याय का शो रूम सजाये बैठा है। ऐसे में कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज भला कैसे पीछे रह सकते हैं, जिनकी जजों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादलों में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके भी बेटे व रिश्तेदार पूरे जोर-शोर से मुंह मांगे दामों पर न्याय बेचने का धंधा करने में जुटे हैं। कई तो पूरे के पूरे खानदान इस व्यवसाय में लगे पड़े हैं, उन्हें और कोई काम सूझता ही नहीं, सूझे भी कैसे, इससे बढ़िया लूट का धंधा और हो भी क्या सकता है ?

हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में तो इन रिश्तेदारों का सिक्का चलता ही है, ज़िला स्तर पर तो इनकी दादागिरी के कहने ही क्या। ये लोग जिस कोर्ट में पेश हो जायें तो वहां का जज सारा कानून भूल जाता है। उसे उस वक्त केवल हाई कोर्ट में बैठा उसका बाप अथवा चाचा-ताऊ ही नज़र आता है। यदि रिश्तेदार ज़रा भी नाराज हो गया तो हाई कोर्ट न जाने कब उसकी गर्दन मरोड़ दे। इस तरह के माहौल में भारत के मुख्य न्यायाधीश बात करते हैं जिला स्तर की न्यायपालिका पर कड़ी निगरानी रखने की।

अभी गत सप्ताह इन्हीं मुख्य न्यायाधीश ने जजों के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही वकालत की ओर भी ध्यान देने की बात कही है। इस संबंध में वे केवल भविष्य में बनने वाले नये जजों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिनके निकट संबंधी वकालत कर रहे हों, उन्हें उसी हाई कोर्ट का जज न बनाया जाये। इससे एक बात तो सिद्ध हो ही गयी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस सच्चाई को समझते हैं कि जजों के रिश्तेदार बाकायदा न्याय की दुकानदारी चला रहे हैं। फिर ऐसे में इसको तुरंत बंद करने के बजाये भविष्य में बंद करने की बात क्यों कही जा रही है ? इसे आज और अभी बंद करने में क्या दिक्कत है ? क्यों नहीं जयपुर हाई कोर्ट के जजों को कोलकाता, कोलकाता वालों को चंडीगढ़ और चंडीगढ़ वालों को मद्रास भेज दिया जाय ?

कानूनन ऐसा कर सकते हैं, करते भी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राज में काफ़ी संख्या में जजों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा भी गया था।

शेष पृष्ठ 2 पर

बुश और ओबामा : एक ही थैली के चट्टे-बट्टे

- मनोज कुमार झा

बराक ओबामा के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ऐसी प्रतिक्रियायें आई हैं और लगातार आ रही हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि एक अश्वेत का राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घटना है। ओबामा के राष्ट्रपति बनने से उत्साहित कतिपय बुद्धिजीवियों - राजनीतिक विश्लेषकों, पत्रकारों, प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि ओबामा जार्ज बुश की नीतियों को पलट देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जार्ज बुश की नीतियां अमेरिका में काफी अलोकप्रिय रहीं। घरेलू मोर्चे पर जहां उन्हें अर्थव्यवस्था में क्रमश: आ रही मंदी से जूझना पड़ा और कर्ज पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता बढ़ी, वहीं वैदेशिक मामलों में अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण ने पूरी दुनिया में उन्हें निंदा का पात्र बना दिया। अमेरिकी हमले के कारण इराक बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान की भी वैसी ही दशा है, पर अमेरिका वहां से टलने का नाम नहीं ले रहा। अफगानिस्तान में जहां अब तालिबान सशक्त हो कर उभर रहे हैं, वहीं इराक में भी उसे विरोधियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसे लगातार धमकाता रहा है और हमला तक करने की चेतावनी देता रहा है। लेकिन ईरान बिना अमेरिका की परवाह किये हुए परमाणु शक्ति हासिल करने के प्रयास में लगा हुआ है।

आज अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने पतनशील दौर में पहुंच चुका है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का जहाज जल्द ही डूबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो महामंदी आई है, उससे निबटने का अमेरिका के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इराक पर हमले में अमेरिका 1000 अरब डॉलर से अधिक कर्ज लेकर खर्च कर चुका है। बुश ने सरकारी कर्ज की सीमा 11,300 अरब डॉलर यानी अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत ज्यादा करने की मांग की थी। इस कर्जे में 24 फीसदी विदेशी बैंकों का है। अमेरिका के ऊपर चीन का 500 अरब डॉलर और जापान का 600 अरब डॉलर बकाया है। वह रूस, ब्राजील और सऊदी अरब का भी कर्जदार है। डॉलर का मूल्य गिरने के कारण कर्ज देने वालों को नुकसान हो रहा है और संभव है कि वे अपना पैसा कहीं और लगायें। इस प्रकार अमेरिका के सामने विकल्प नहीं के बराबर हैं। युद्ध साम्राज्यवादी व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। युद्धों के बिना इस व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए साम्राज्यवादी व्यवस्था के नये प्रतिनिधि बराक ओबामा शीघ्र इराक और अफगानिस्तान से हट पायेंगे, इसमें संदेह है। यद्यपि अमेरिकी जनमत युद्ध को जारी रखने के पक्ष में नहीं है, इसलिए ओबामा पर इराक और अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने का दबाव तो बढ़ेगा ही, पर ये ऐसा कर नहीं पायेंगे। इराक में सिर्फ अमेरिकी सेना ही नहीं काबिज़ है, बल्कि तेल कंपनियां भी जो वहां से बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। उनका दबाव अमेरिका को वहां से हटने नहीं देगा। वास्तव में इराक पतन की ओर तेजी से अग्रसर अमेरिकी साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक उपनिवेश बन गया है। लेकिन वहां और अफगानिस्तान में भी उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई तालिबान के प्रमुख मुल्ला उमर को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो अमेरिका के दुश्मन नंबर-1 ओसामा बिन लादेन का खास आदमी और संबंधी भी है। अमेरिका ने आतंकवाद का ऐसा राक्षस खड़ा कर दिया है जो अब पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। अमेरिका जिन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लगते सीमा क्षेत्र पर मिसाइलें दाग रहा है, उन्हें पैदा भी उसी ने किया है।

सवाल है, क्या हनुमान जी की मूर्ति सदा साथ रखने वाले बराक ओबामा इन समस्याओं पर काबू पा सकेंगे और यदि हां, तो कैसे ? यह ऐसा यक्षप्रश्न है जिसका जवाब न तो ओबामा के पास है और न ही उनकी जीत को एक क्रांति मानने वाले उन बुद्धिजीवियों के पास जो भेड़चाल में शामिल होने में सबसे आगे रहना चाहते हैं।

यह ठीक है ओबामा पहले ऐसे अश्वेत

शेष पृष्ठ 2 पर